P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-12* August- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

कोविड–19 और भारतीय अर्थव्यवस्था

Covid-19 and Indian Economy

Paper Submission: 12/08/2020, Date of Acceptance: 24/08/2020, Date of Publication: 25/08/2020

रीता सिंह
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
एम.जी. शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय,
खरसिया, रायगढ़, भारत

सारांश

कोरोना महासंक्रमण ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब–जब मनुष्य ने प्रकृति से कृतघ्नता की है उसे प्रकृति के दण्ड को भुगतना ही पड़ा है। आर्थिक गतिविधियों के कारण हुए नुकसान की भरपाई हम कुछ वर्षों में भले ही कर लेंगे, परन्तु मानसिक अशांति या कोविड–19 की भयानकता को मानव अपने इस जन्म में तो नहीं ही भूल सकता। बावजूद इसके लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही से बहुत अधिक नुकसान होने की आशंका है। संसाधनों की सीमितता के बावजूद केन्द्र के साथ–साथ राज्य सरकारों को भी बिना किसी राजनीतिक दांवपेंच के समाधान हेतु आगे आना होगा। मनरेगा के साथ ही एम.एस.एम.ई. को राहत पैकेज के साथ अपनी गतिविधियों की नियमित समीक्षा करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना संभव है।

The Corona Pandemic has made us think that whenever man has gratitude with nature, he has to pay the penalty. We can compensate the loss due to Economic activities in few years but mental disturbance due to Covid-19 cannot be forgotten in lifetime. Despite this the negligence of people is causing a lot of damage. Inspite of limited resources, the Central as well as the State Governments will have to come forward to find the solution without any political agenda. Along with M.N.R.E.G.A. and relief package to M.S.M.E. should be regularly appraised from time to time. Only then it is possible to bring back economy on track.

मुख्य शब्द : अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कोविड–19, लॉकडाउन, फिजिकल डिस्टेसिंग, आत्मनिर्भरता ।
Economy, Economic Crisis, Covid-19, Lockdown, Physical Distancing, Self-dependence.

प्रस्तावना

मार्च 2020 के पहले तक हमारी जिदंगी अच्छी चल रही थी, पिछले 08 दशकों में देखें तो सबसे बड़ा संकट 1929 का संकट था।

आधुनिक मानव के विकास और कल्याण में अर्थशास्त्र ने अहम भूमिका निभाई है। मानव जीवन आर्थिक ढांचे पर सवार होकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। मानव जंगली जानवरों के आखेट, मछली पकड़ने, कंदमूल फल सब्जियों के साथ ही कृषि अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व भी करीब 1000 वर्षों तक कायम रहा। भंडारण और सामुदायीकरण ने सामूहिकता को सुगम बनाया।

करीब 3000 साल पहले पहिये के आविष्कार और उसके बाद भाप इंजन और बारूद की खोज ने विश्व अर्थव्यवस्था की काया ही पलट कर रख दी। इसमें औद्योगिक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। मगर सूचना अर्थव्यवस्था से महज 2 शताब्दियों के दौरान ग्लोबल वैल्यू चैन का सृजन हुआ, इसने बाजारों को जोड़ दिया। पूरा का पूरा विश्व एक गांव में सिमट गया। वास्तव में इसने उपभोग को बढ़ाया, आराम और सुकून को बढ़ाकर आनंद में वृद्धि की और अब आनंद की इस खोज ने उन्माद का रूप धारण करके पृथ्वी को ही विनाश की ओर ढकेल दिया।

जब–जब प्रकृति के संतुलन में मानव का नाजायज हस्तक्षेप हुआ है, प्रकृति ने हमेशा दण्डित किया है पिछले कई दशकों से हम इनके दिये दण्ड को बारी–बारी से भुगत रहे हैं। 2004 में हिंद महासागर का सबसे बड़ा भूकंप जिसके कारण सुनामी, उत्तराखण्ड में भूस्खलन 1998, केदारनाथ आपदा 2013 .. .

अंतरिक्ष में किए जाने वाले हस्तक्षेप भी आपदाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। और अब आया है कोरोना .....

हमारी गलतियों, निर्दयता, अतिक्रमण, प्रकृति से कृतघ्नता जीवों से उनके जीने का हक छीनने का दण्ड, कठोर दण्ड देने, सबक सिखाने।

कोरोना वायरस, वायरस का एक बड़ा परिवार है जो बीमारी का कारण बनता है, अभी तक मानव में नहीं पाया गया था। 2020 में चीन में उपजे स्वास्थ्य संकट ने दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण फैला दिया।

साहित्यावलोकन (Review of literature)

रूचि सैनी (मई 2020)– इन्होंने अपने अध्ययन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कोरोना वायरस के प्रभाव की चर्चा की है।

संजय सिंह (20 अप्रैल 2020) – संजय सिंह ने अपने अध्ययन में बताया कि आर्थिकी को संभालने के लिए भारत में प्रतिभाशाली अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें प्रोफेशनल हों और वे भारतीय चुनौतियों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से नीतिगत समाधान सरकार के सामने रखें।

हिमांशु शेखर (28 अप्रैल 2020) – इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस भारतीय राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर सकता है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (3 अगस्त 2020)– पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अनुसार इस चुनौतीपूर्ण समय में विश्वास को बहाल करने की सख्त आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण लुब्रिकेंट का काम करता है।

उद्देश्य (Objective)

आज मानव प्रकृति से छेड़छाड़ की इस भयानकता से जुझ रहा है, अभी भी समय है कि वह अपनी संस्कृति को पहचाने, समझे और उसका अनुसरण करें।

समस्या (Problems)

इस संक्रमण ने विश्व के साथ–साथ भारत में भी कहर बरपाया हुआ है।

इस संकट से निपटने के लिए विश्व के बहुत से देशों ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। जिसकी वजह से विश्व एक बार फिर आर्थिक महा संकट के दौर से गुजर रहा है। बाजार में गिरावट आने लगी है, अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी और सब कुछ ठहर सा गया है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तों ''सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी'' के जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है।

फिलहाल W.H.O. की माने तो कोविड–19 में संकट का सबसे बुरा दौर आना बाकी है, हम सिर्फ कयास लगा सकते है पर निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हां यह जरूर स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की मांग एवं पूर्ति आधारित सुस्ती के साथ–साथ बेरोजगारी का भीषण संकट आ रहा है।

फिजिकल डिस्टेसिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, जिससे लोगों को घर पर ही रहना होगा। लोग यदि घर पर रहेंगे तो वह बाहर जाकर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे सिमेमा हॉल, जिम, मॉल्स, होटल, सैलून, कपड़े, आभूषण और तमाम तरह की दुकानें महामारी के असर से ग्रस्त रहेंगी। राज्य जो आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिनाडु जब तक इन राज्यों में महामारी की मार कम नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से चलना मुमकिन नहीं है।

कारोबारियों ने लागत में कटौती करने के लिए कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोग पहले ही अपनी नौकरी खो चुके हैं, बड़े शहरों से प्रवासी मजदूर अपने मूल स्थानों की ओर जा चुके हैं क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नही।

जो लोग कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकल रहे हैं वे तनख्वाह में कटौती कर रहे हैं ऐसे में बुनियादी आवश्यकता के अलावा लोग अन्य चीजों को नहीं खरीदेंगे।

महामारी के प्रकोप से पहले ही लोगों के मन में स्लोडाउन को लेकर भय बैठ गया था, अब मंदी को लेकर लोगों के मन में आशंका है, लोगों की नौकरियां जा रही है, वेतन में कटौती हो रही है, बहुत सारे लोगों का धंधा मंदा पड़ रहा है, विशेषकर छोटे व्यापारी जिनके पास अतिरिक्त पूंजी नहीं है और जो पैसा आता है उसी से उन्हें अपने वर्कर को वेतन देना पड़ता है और बाकी के खर्चे करने पड़ते हैं आवक बंद होने से उनकी स्थिति अत्यंत सोचनीय है ऐसे में आर्थिक अस्तित्व को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है।

विश्व बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है, इससे देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन 1991 की उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहेगा।

यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते है।

कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण और मृतकों की संख्या में वृद्धि के साथ ही कोविड–19 महामारी अपना प्रकोप बढ़ाती जा रही है। लोग इससे विचलित हो गए हैं। यह संकट समाज में अनेक प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। स्कूल कॉलेज एवं सभी प्रकार के संस्थान पूर्णतः बंद है। ऐसे पूर्ण बंदी के समय जब परिवार के सदस्य अपना पूरा समय घर पर एक साथ बिता रहे हैं तो आपस मैं सामंजस्य बैठाना कई परिवारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना गया है। पारिवारिक सामंजस्य चुनौतीपूर्ण होने के कारण मानसिक अशांति है। अभिभावक आर्थिक परेशानियां एवं कार्य की अधिकता से जूझ रहे हैं। साथ ही अधिक उर्जा वाले बच्चे घर में अपनी उर्जा का उपयोग कर पाने में अक्षम हैं क्योंकि उनके खेल अन्य सदस्यों के कार्यों में व्यवधान कर रहे हैं। कामकाजी परिवारों में माता–पिता ने माना कि वे अपने काम के दबाव के कारण अपने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण समय नहीं दे पा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि अपने काम के साथ–साथ बच्चों की ऑनलाईन

कक्षाओं को व्यवस्थित कर पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। बच्चे ऑनलाईन कक्षाओं के बाद भी मोबाईल और लैपटॉप में सोशल मीडिया में अपना समय बिता रहे हैं। बहुत सी महिलाओं ने यह भी माना कि अपने ऑफिस के काम में डिस्टर्बेंस से बचने के लिए वे खुद बच्चों को मोबाईल दे देती है ताकि वे अपने काम पर ध्यान दे सकें।

प्रश्न यह उठता है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में बच्चों की विकास को सही आकार देने के लिए समाधान की आवश्यकता है, ताकि संकट के इस समय में पारिवारिक प्रेम को बनाए रखा जा सके।

हालांकि इस कोविड–19 महामारी में शारीरिक दूरी के नियम के पालन और मास्क के उपयोग की महत्ता से सभी परिचित हैं, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बहुत से लोग लापरवाही का भी परिचय दे रहे हैं यह लापरवाही अक्षम्य हैं क्योंकि लोग एक तरह से जान बूझकर खुद के साथ–साथ दूसरों के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। निसंदेह हालात तेजी से बदल सकते हैं यदि हर कोई मास्क का इस्तेमाल करें और शारीरिक दूरी को लेकर सतर्क हो जाए। इसकी जरूरत इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि इतने बड़े देश में सामूहिक स्तर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने में लंबा समय लगेगा और तब तक कहीं अधिक नुकसान हो चुका होगा।

प्रभाव (Effect)

कामगारों का अपने गांव शहर से रोजी रोजगार की तलाश में बाहर जाना एक सहज सामाजिक प्रक्रिया रही है, वह जिस महानगर में जाते हैं वहां मेहनत कर उसे धनी और बेहतर बनाते हैं।

कामगारों के रोजगार की तलाश में बाहर जाने की इस सहज सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया में एक बड़ा उथल पुथल कोरोना महामारी आने से हुआ। आज जहां रोजगार है वहां से कामगार लौट–लौट कर अपने घर आ चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार लॉकडाउन के बाद दो करोड़ से ज्यादा प्रवासी कामगार अपने गांव शहर स्थित घर लौट आए हैं और इनमें से 60 प्रतिशत अब अपने गृह क्षेत्र में ही रह कर गुजर–बसर करना चाहते हैं बाकी का मानना है कि गृह क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तब रोजगार के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा।

अच्छी बात यह हुई कि कुछ राज्य सरकारों ने बड़े शहरों से लौट रहे अपने राज्य केप्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराने को अपना नैतिक दायित्व मानकर इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इन कामगारों को समायोजित करने में आज सबसे मददगार मनरेगा कार्यक्रम है। एक अन्य विकल्प विभिन्न पंचायतों के आजीविका मिशन के तहत हो रहे काम है। इसके साथ ही सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम**(एम.एस.एम.ई.)** का सहयोग कर केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों में ऐसे कामगारों के लिए रोजगार के अवसर उन्हीं के राज्य गृह नगर में सृजित करने के विकल्प को भी विकसित करने में लगी है।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाऐं
वर्गीकरण

उद्यम श्रेणी	विनिर्माण क्षेत्र संयंत्र व मशीनरी में निवेश
1. सूक्ष्म उद्यम	पच्चीस लाख से अधिक नहीं।
2. लघु उद्यम	पच्चीस लाख से अधिक लेकिन पांच करोड़ रू. से कम।
3. मध्यम	पांच करोड़ रू. से अधिक लेकिन दस करोड़ से रूपये से कम ।

उद्यम श्रेणी	उपस्करों में निवेश
सूक्ष्म उद्यम	दस लाख रूपसे से कम
लघु उद्यम	दस लाख रूपये से अधिक लेकिन दो करोड़ रूपये से कम
मध्यम उद्यम	दो करोड़ रूपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रूपये से कम

एम.एस.एम.ई. के संवर्धन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, तथापि भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका उद्यमिता रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एम.एस.एम.ई. के प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के राज्यों के प्रयासों में सहायता करना है।

630.52 लाख अनुमानित उद्यमों वाले सुक्ष्म क्षेत्र एम.एस.एम.ई. की कुल अनुमानित संख्या 99 प्रतिशत से अधिक है। 3.31 लाख वाले लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एम.एस.एम.ई. वाले मध्यम क्षेत्र कुल अनुमानित एम.एस.एम.ई. का क्रमशः 0.52 और 0.01 हिस्सा है। एम. एस.एम.ई. की अनुमानित संख्या 633.38 लाख में से 324. 88 लाख एम.एस.एम.ई. (51.25%) ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा 309 लाख एम.एस.एम.ई. (48.75%) शहरी क्षेत्रों में हैं।

श्रेणी वार उद्यमों का विवरण

(संख्या लाख में)

श्रेणीवार उद्यमों का विवरण					
क्षेत्र	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**	**हिस्सा (%)**
01	02	03	04	05	06
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

अभी तक स्किल मैपिंग से जो आंकड़े उभर रहे हैं उससे लगता है कि शहरों से लौटे ज्यादातर कामगार कुशल श्रमिक है उन्हें पुनर्वासित करना एक समस्या भी है और एक अवसर भी। भवन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेशन, पर्यटन व्यवसाय की दक्षता वाले कामगारों के लिए राज्य सरकारों को काम के अवसर सृजित करने होंगे क्योंकि मनरेगा से उन्हें मन मुताबिक एवं योग्यता अनुसार काम मिलना मुश्किल होगा। जो व्यक्ति दिल्ली मुंबई जैसे किसी महानगर में अपनी योग्यता के आधार पर वर्षों से काम कर रहा था अब वह मनरेगा के तहत अपने गांव में गड्ढे नहीं खो सकता यह उसकी योग्यता का अपमान होगा।

सरकारी विकल्पों की सीमित होने के कारण उनमें से अनेक को फिर भी उन्हीं खेतों में काम करना

होगा जिन्हें वे बेहतर मूल्य ना मिल पाने के कारण छोड़कर शहर गये थे। हालांकि कोरोना संकट के कामगारों की प्राथमिकता पहले अपनी जान एवं शरीर की रक्षा करनी है फिर रोजगार के लिए बेहतर विकल्प की तलाश करना। ऐसे में संभव है कुछ कम पैसे पाकर भी उनमें से ज्यादातर अपने गांव शहर के आस–पास ही अपने लिए रोजगार तलाशना चाहेंगे। वही जो फिर से महानगरों एवं अन्य राज्यों में जायेंगे, वहां वे अपनी कंपनी के मालिक से मेहनताना के साथ–साथ अपने रहने के लिए साफ सुथरी जगह व अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग भी करेंगे।

कोविड–19 में उपजा आर्थिक संकट विश्वव्यापी है। इस संकट से दूर संचार स्वास्थ्य और बीमा सेवाएं यह तीन क्षेत्र प्रमुखता से प्रभावित हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि कोविड–19 संकट के दौरान जेब में पैसे हो तो भी हम रेस्टोरेंट पर बैठकर एक साथ खाना नहीं खा सकते हैं।

इस चुनौती से निपटने के लिए भारत को सबसे पहले इस महामारी को और फैलने से रोकना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिल सके। साथ ही भारत को लघु एवं मझोले उद्योग को भी बचाना होगा। इसके लिए व्यापक रणनीति भी तत्काल तैयार करना होगी। राहत पैकेज का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र पर केंद्रित करना होगा। सरकारी खजाने पर दबाव होने के बावजूद खुले हाथों से मदद करने से कोई कोताही नहीं की जानी चाहिए। सभी लोग और उद्योगों को इसके दायरे में लाना होगा ताकि वह कर्ज के बोझ तले आर्थिक रूप से दम ना तोड़ दे।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके उपाय वास्तव में असरकारी साबित हो। उसका सबसे अधिक ध्यान छोटे और मझौले उद्योगों को सहारा देने पर होना चाहिए, क्योंकि महामारी की मार उन पर ही सबसे ज्यादा पड़ी है। बहुत से उद्योगों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे का अभाव है, इस अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने वाले उपाय करना चाहिए, अन्यथा कामगारों की छटनी की नौबत आ सकती है। सरकार के लिए यह समय तेजी से योजना बनाने और उन्हें लागू करने का है ताकि जमीनी स्तर तक उनका असर दिखना शुरू हो और अर्थव्यवस्था को राहत मिले।

स्पष्ट है कि कोरोना वायरस जल्द जाने वाला नहीं है अतः अन्य लोगों की तरह अब हमें कोविड–19 के साथ ही जीना होगा। हमें अपने रहन–सहन आदतों और सोच को बदलना होगा। यह निराशाजनक है कि सावधानी बरतने की बजाय लापरवाही का परिचय दिया जा रहा है, समझना कठिन है कि मास्क लगाने सेहत साफ–सफाई को लेकर सतर्क रहने और एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाने के प्रति सजगता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। लाईलाज बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाने के प्रति सचेत नहीं दिख रहे हैं, यह लापरवाही कोरोना से लड़ाई को कठिन बनाने और साथ ही देश की समस्याओं को बढ़ाने का काम कर रही है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और कुछ शहरों में संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक है। लेकिन यह अत्यंत उल्लेखनीय है कि अपने देश में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। बड़ी आबादी के साथ जनसंख्या के घनत्व और कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद यदि अन्य देशों के मुकाबले भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या कम है तो इसका मतलब है कि या तो जलवायु ने भारत की मदद की अथवा यहां के लोगों की जीवनशैली ने या फिर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने। किन्तु कोरोना से आसानी से छुटकारा मिलने वाला नहीं, अतः समझदारी इसी में है कि उससे बचने के तौर–तरीकों को जीवन का हिस्सा बना लिया जाए।

उपाय

यदि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगानी है तो केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों को भी नए सिरे से कमर कसनी होगी। राज्यों को इसका आभास होना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को थामने के मामले में लापरवाही का मतलब है संकट को बढ़ने देना। सबको कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को जीतने के लिए यह भी आवश्यक है कि सरकार के साथ–साथ आम जनता भी सतर्कता का परिचय दे। यह गलत है कि खतरा सामने नजर आने के बावजूद लोग अपेक्षित सजगता नहीं दिखा रहे। लोगों को समझना होगा कि यह लड़ाई उनके सहयोग के बिना नहीं लड़ी जा सकती है।

इस महामारी के कारण विश्व के अधिकांश देशों द्वारा चीनी उत्पादों का बायकाट करने से चीनी उत्पादों की मांग पर गहरी चोट पड़ी है, साथ ही सीमा पर उलझने की वजह से विश्व के देश उसे विलेन के रूप में देख रहे हैं भारत ने चीन के खिलाफ सामरिक कदमों के साथ ही कई सख्त आर्थिक कदम भी उठाए हैं। 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिये गये, विश्व के कई देशों का रवैया भी चीन के साथ कठोर बना हुआ है। इस सब का नतीजा है कि आज चीन की कई कंपनियाँ दिवालिया और जप्त होने की कगार पर है। चीन का संकट भारत के लिए अवसर बना सकता है भारत अगर अपने मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करें और स्थानीय समेत वैश्विक बाजार को रीजनेबल उत्पाद उपलब्ध कराए तो भारत सॉफ्टवेयर के साथ विनिर्माण क्षेत्र में भी विश्व बाजार में वांछित मुकाम हांसिल कर सकता है।

वास्तव में यह समय उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है। लेकिन इसमें जिस नौकरशाही को महती भूमिका निभानी है, उसके रवैया से यह नहीं लगता कि वह कोरोना संकट को एक अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। बातें तो खूब हो रही है कि सरकारी तंत्र चीन से निकलने वाली कंपनियाँ को देश में आकर्षित करने के लिए सक्रिय है लेकिन यह सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आती, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों आनन–फानन चीन से निकलना चाहती है इसलिए जरूरत इस बात की है कि इसके अनुकूल माहौल तैयार करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जाए ऐसा इसलिए और आवश्यक है क्योंकि इन कंपनियों के पास ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड वियतनाम आदि देश विकल्प के रूप में मौजूद है। हमारी नौकरशाही खुद से सवाल करें कि

आखिर बीते चार पांच महीने में कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत की ओर रूख किया है? निसंदेह केन्द्र और राज्य सरकारों को भी इसकी खोज खबर लेनी चाहिए कि उनकी ओर से आपदा अवसर में बदलने के बारे में जो कहा जा रहा है नौकरशाही उस पर अमल कर रहा है या नहीं। यदि यह समझा जा रहा है कि कुछ नीतिगत घोषणायें कर देने से चीन छोड़ने को तैयार बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत आ जायेंगी तो यह मुमकिन नहीं है। इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

यह सही है कि विदेशी कंपनियों के लिए आवश्यक सुविधाएं रातों रात नहीं जुटाई जा सकती लेकिन ऐसा करने की प्रबल इच्छा शक्ति का प्रदर्शन तो किया ही जा सकता है। इससे ही हालात बदलेंगे और चीन छोड़ने का मन बना चुकी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भारत आने को तैयार होंगी। यदि इन कंपनियों को आकर्षित करने में देरी होती है तो उन्हें भारत लाने में वांछित सफलता नहीं मिलती तो यह एक तरह से एक बड़े अवसर को खोने जैसा ही होगा। साथ ही जब आर्थिक परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती है कि नई योजनाएं शुरू की जा सके, तो फिर उचित यही है कि उन्हीं योजनाओं पर ही अधिक बल दिया जाए जो संकट के समाधान में सहायक हो सकते हैं। इसी इरादे से आत्मनिर्भर भारत अभियान पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अभियान के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को प्राथमिकता दी जायेगी, क्योंकि कोरोना की मार सबसे अधिक कमजोर वर्ग पर ही है, इसलिए उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसमें राज्य सरकारों को भी शामिल होना चाहिए।

'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' के तहत बड़े पैमाने पर मैपिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोरोना महामारी के कारण वापस लौटे श्रमिकों को गांव में ही उनके आसपास रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है।

बेहतर होगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें एक टीम की तरह काम करें। सक्षम आधारभूत ढांचे और तकनीक आधारित व्यवस्था का निर्माण आनन–फानन में नहीं हो सकता, लेकिन यह आवश्यक है कि जहां तक संभव हो सके हम आयात पर अपनी निर्भरता कम करें और इनकी नियमित समीक्षा होती रहनी चाहिए, ताकि किसी तरह का संशय उत्पन्न ना हो और यह अभियान सही गति से आगे बढ़े।

कोविड–19 महामारी से लड़ने में आर.टी.आई. और एन.एस.टी. आई. द्वारा कई इनोवेशन भी हुए है। लो कॉस्ट रोबोट, फेस शील्ड एरोसॉल बॉक्स, स्वैब, स्वैब टेस्टिंग के लिए मोबाईल क्यूबिल, यूवी सैनिटाईजर बनाए गये हैं। माइक्रोवेब ओवन को सैनिटाइजेशन चेंबर बनाकर चिकित्सा कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए दिया गया है, सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाकर थानों में लगाए गये हैं । कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय पी.एम.के.वी. वाई. के साथ कार्य कर रहा है।

कोरोना महामारी के बाद भारत के पास एक ऐसी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का अवसर है जो दुनिया के लिए लाभकारी और आकर्षक हो सकती है। इसमें दो मत नहीं कि कोविड–19 की चुनौतियों के बीच सरकार ने नए आत्मनिर्भर भारत पैकेज से एम.एस.एम.ई.को बड़ी राहत दी है, लेकिन कोरोना संकट लॉकडाउन और श्रमिकों के पलायन ने छोटे उद्योग कारोबार क्षेत्र को गंभीर चुनौतियों के दौर में पहुंचा दिया है। यद्यपि सरकार ने एम.एस.एम.ई.इकाईयों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बैंकों के जरिए बगैर किसी जमानत के आसान ऋण की राह खोली है लेकिन अधिकांश बैंक ऋण डूबने की आशंका के मद्देनजर ऋण देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एम.एस.एम.ई.की आधे से अधिक इकाइयां उत्पादन शुरू नहीं कर पाई है, जिनमें काम शुरू हुआ है वह भी काफी कम क्षमता के साथ परिचालन कर रही है उनके सामने कच्चे माल की समस्या है। मजदूरों की कम उपलब्धता के कारण भी उनकी उपदकता पर काफी असर पड़ा है।

निःसंदेह कोविड–19 के प्रकोप से पहले ही सुस्त गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था को संभालना और इसे पुनः पहले जैसी स्थिति में लाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार द्वारा दिये गये नए आर्थिक पैकेज से छोटे उद्योग अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाते दिखेंगे। ऐसे में यह अत्याधिक जरूरी है कि सबसे पहले सरकार एम.एस.एम.ई.के लिए हाल ही में घोषित की गई राहतों के क्रियान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़े, खासतौर से बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे बिना डरे बिना जमानत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को आसान ऋण देने के लिए पर आगे बढ़े, क्योंकि एम.एस.एम.ई.को दिये जाने वाले कर्ज की जमानतदार स्वयं सरकार है। जरूरत है उसके कारगर क्रियान्वयन की इससे इस समय देश की ठप पड़ी अर्थव्यवस्था गतिशील होगी और देश विकास की डगर पर आगे बढेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब देश में उद्योग, कारोबारी गति को पुनः गति देने का समय है, इसी के जरिए बाजार में तेजी आयेगी। तमाम सेक्टर के रोजगार के मोर्चे पर जो अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। अर्थव्यवस्था का पहिया पुनः सुचारू रूप से घुमने से उनके छटने में भी मदद मिलेगी।

निष्कर्ष (Conclusion)

आज विश्व जिस कोरोना महामारी से त्रस्त है उसका मूल कारण मानव द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ ही है। योग वशिष्ट में श्री राम को गुरू वशिष्ट ने उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि जो व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति का प्रकृति के साथ तालमेल कर लेता है उसी का जीवन सफल होता है।

भारत में व्यापारिक मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं चलता, सांस्कृतिक मूल्यों और मानवता के आधार पर चलता है इसलिए यहां शुभ–लाभ की परंपरा चली आ रही है, अर्थात् ऐसा लाभ जो शुभ हो। यही कारण है कि पैदल जा रहे मजूदरों की सेवा में समाज निकल कर

आया। यह वही है जो आत्मनिर्भर भारत ही वास्तव में सशक्त सच्चा और योग्य भारत होगा।

सुझाव (Suggestions)

आज हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने की जद्दोजहद में उलझे हुए है, परन्तु जरूरत इस बात की है कि आर्थिक के साथ–साथ मानसिक तौर पर एक कमजोर और निराश समाज को उबारने का उपाय करें, जो आघात इंसान के मन पर पहूंच रहा है, या पहुंचेगा, उससे कैसे निपटा जाए इसका आकलन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मनिर्भरता का तात्पर्य व्यापार और रोजगार नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का तात्पर्य स्वाभिमान और आत्मरक्षा है।

किसी ने सही कहा है– **''आपदा हमारे लिए कई दरवाजे बंद करती है तो कुछ खोलती भी है''**–

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *M. jagaranjosh.com*
2. *M.economictimes.com*
3. *Https/www.bbc.com*
4. *wwwnaidunia.com*
5. *haribhumi.com*
6. *M.uttamhindu.com*
7. *orfonline.org*